सेबी के आदेश को एनएसई देगा चुनौती

मुंबई, प्रेट्र : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शुक्रवार को कहा कि को-लोकेशन मामले में वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को सिक्युरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) में चुनौती देगा। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि सेबी के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार हैं। सेबी ने इस मामले में अप्रैल में दिए गए आदेश में एनएसई को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ को जमा करने के लिए कहा था।

टेलीकॉम कंपनियों को आइपीआर पर 10 फीसद तक खर्च करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि भविष्य के उत्पादों का निर्माण भारत में ही हो।

– अंशु प्रकाश
अतिरिक्त सचिव, टेलीकॉम

सेंसेक्स	37,930.77	537.29
निफ्टी	11,407.15	150.05
सोना प्रति दस ग्राम	₹33,170	₹160
चांदी प्रति किलोग्राम	₹37,625	₹625
डॉलर	₹70.23	₹0.20
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 72.66	

संकेत ▶ निवेशकों को स्थिर सरकार की उम्मीद, 23 मई को आने हैं चुनाव नतीजे

आम चुनाव में अनुकूल नतीजे की आस में सेंसेक्स 537 अंक उछला

पूरे सप्ताह में सेंसेक्स 467 .78 अंक और निफ्टी 128 .25 अंक मजबूत

मुंबई, प्रेट्र : आम चुनाव के नतीजे कारोबारियों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद में देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को भारी उछाल दर्ज किया गया। इस दौरान शेयरों में चौतरफा खरीदारी हुई। बीएसई का सेंसेक्स 537.29 अंकों की तेजी के साथ 37,930.77 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 150.05 अंकों की तेजी के साथ 11,407.15 पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह के कारोबार में सेंसेक्स कुल 467.78 अंक और निफ्टी 128.25 अंक मजबूत हुआ।

सेंट्रम ब्रोकिंग के सीनियर वीपी और रिसर्च (वेल्थ) सेगमेंट के प्रमुख जगन्नाथन थुनुगुंटला ने कहा कि रविवार को मतदान के आखिरी चरण से पहले बाजार में हुई चौतरफा खरीदारी बताती है कि निवेशकों को स्थिर सरकार बनने का अनुमान है।

सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस में सर्वाधिक 6.09 फीसद तेजी रही। हीरो मोटोकॉर्प 4.26 फीसद उछला। मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज ऑटो में तीन फीसद से अधिक तेजी रही। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 2.36 फीसद गिरावट रही। बजाज फाइनेंस में गुरुवार को भी चार फीसद उछाल दर्ज किया गया था। गुरुवार को ही कंपनी ने मार्च तिमाही के शुद्ध लाभ में एकल आधार पर 50 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की थी।

बीएसई पर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज 1.2 फीसद लुढ़का। कंपनी ने मार्च तिमाही के समेकित शुद्ध लाभ में 78.81 फीसद गिरावट दर्ज की है। कंपनी का तिमाही नतीजा गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुआ था। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 5.24 फीसद गिरावट के साथ 75 रुपये का निचला स्तर छू लिया था, जो इसका एक साल का निचला स्तर है।

बजाज ऑटो बीएसई पर 3.30 फीसद उछला। कंपनी ने मार्च तिमाही के शुद्ध लाभ में 19.82 फीसद बढ़ोतरी दर्ज की है। रिलायंस कैपिटल में बीएसई पर 2.18 फीसद तेजी दर्ज की गई। कंपनी ने निप्पों लाइफ इंश्योरेंस को रिलायंस निप्पों लाइफ असेट मैनेजमेंट में अपनी 42.88 फीसद तक हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के ऑटो सेक्टर में सर्वाधिक 2.45 फीसद तेजी रही। बैंकिंग, फाइनेंस और एफएमसीजी सेक्टर्स में भी दो फीसद से अधिक उछाल रहा। दूसरी ओर हेल्थकेयर में सर्वाधिक 0.99 फीसद गिरावट रही।

एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में जापान के बाजार में तेजी रही, जबकि चीन और कोरिया के बाजारों में गिरावट रही। प्रमुख यूरोपीय बाजार भी गिरावट के साथ खुले।

अमेरिका करेगा ईरान से बाधित तेल आपूर्ति की भरपाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इंडियन ऑयल ने अमेरिका से पहली बार किया तेल खरीद समझौता
- पिछले वर्ष 90 लाख टन खरीदा था ईरान से, अब इसका आधा अमेरिका से खरीदेगी कंपनी

अब धीरे-धीरे यह साफ होता जा रहा है कि ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत के लिए अमेरिका एक बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभर रहा है। इसका उदाहरण यह है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) जितना कच्चा तेल ईरान से खरीदती रही थी, अब उसका करीब आधा अमेरिका से खरीदेगी। आइओसी ने पहली बार अमेरिका की दो कंपनियों से तेल खरीदने का समझौता किया है जिसके मुताबिक इस वर्ष 46 लाख टन क्रूड की खरीद की जाएगी। पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में आइओसी ने ईरान से 90 लाख टन कच्चा तेल खरीदा था। अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से मई, 2019 से आइओसी समेत कोई भी भारतीय कंपनी ईरान से क्रूड नहीं खरीद रही हैं।

आइओसी व अन्य भारतीय कंपनियां पहले भी अमेरिका से तेल खरीदती रही हैं। वर्ष 2017-18 में पहली बार भारत ने अमेरिका से तेल खरीदा था। अमेरिका ने हाल ही में क्रूड का आयात भी शुरू किया है और उसके लिए भारत जैसे बड़े बाजार को तेल बेचना फायदे का सौदा है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारतीय कंपनियों के लिए ईरान से तेल खरीदना मुश्किल हो गया है। वर्ष 2018-19 में ईरान से 2.4 करोड़ टन तेल खरीदा गया था। इसमें 90 लाख टन अकेले आइओसी ने खरीदा था। आइओसी के चेयरमैन संजीव सिंह का कहना है कि पहली बार अमेरिका से तेल खरीद का समझौता किया गया है। वैसे, ईरान से जितनी मात्रा में तेल खरीदा जाता रहा है उसकी भरपाई किसी एक देश से होना मुश्किल है इसलिए कई आपूर्तिकर्ताओं से बात हो रही है। आइओसी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने आश्वस्त किया कि देश में तेल आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी।

आइओसी के निदेशक (रिफाइनरी) एके शर्मा ने कहा, 'तकरीबन 20 लाख टन अतिरिक्त तेल सऊदी अरब से लिया जा सकता है। इस वर्ष सऊदी अरब से 56 लाख टन तेल खरीदने का समझौता किया गया है।' आइओसी के अधिकारी मानते हैं कि ईरान से तेल खरीदना काफी आसान था। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भारतीय कंपनियां ईरान से तेल खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकतीं। आइओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस जैसी कंपनियों की रिफाइनरी का कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर का है।

इंडियन ऑयल को 6,099 करोड़ रुपये लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसी) को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में 6,099.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी को हुए शुद्ध लाभ से 16.88 फीसद ज्यादा है। हालांकि कंपनी की रिफाइनरी मार्जिन बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन इनवेंटरी और फॉरेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा विनिमय) से संबंधित लाभ के चलते कंपनी बेहतर नतीजे दे पाई।

राणा कपूर से 1.44 करोड़ का बोनस वापस लेगा यस बैंक

- बैंक का बोर्ड वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दिया बोनस वसूलने के लिए तैयार
- कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी आरबीआइ की नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के कर्जदाता यस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निर्देश के बाद अपने पूर्व प्रमुख राणा कपूर को दिया गया 1.44 करोड़ रुपये का बोनस वापस लेने का फैसला किया है। फंसे कर्ज (एनपीए) के संकट से जूझ रहा बैंक अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस की लचरता मामले में भी आरबीआइ के निशाने पर है। पिछले वर्ष अक्टूबर में आरबीआइ ने कपूर को एमडी पद से हटने का निर्देश दिया गया था। आरबीआइ ने यह सुझाव भी दिया था कि कपूर को दिए गए बोनस की भी वसूली की जाए। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने आरबीआइ के निर्देश पर राणा कपूर को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में जो भी बोनस दिया था, उसे वापस लेने का विचार स्वीकार कर लिया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कपूर का कार्यकाल खत्म होने के बाद आरबीआइ उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहती थी। हालांकि इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि एनपीए की गलत रिपोर्टिंग और गवर्नेंस को लेकर शिकायतों की वजह से उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया।

प्रबंधन स्तर पर फेरबदल : निजी क्षेत्र का यह बैंक अपने कामकाज को लेकर काफी सुर्खियों में रहा। एनपीए और गवर्नेंस को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद राणा कपूर के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हुई। इस प्रक्रिया के तहत रवनीत सिंह गिल को बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया। और बैंक में प्रबंधन स्तर पर काफी फेरबदल देखा गया। इसी सप्ताह आरबीआइ ने अपने एक पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है।

जेट एयरवेज के बोर्ड से एतिहाद के नामित निदेशक का इस्तीफा

- कंपनी के निदेशक मंडल में केवल अशोक चावला और शरद शर्मा बचे
- एतिहाद के एक अन्य नामित निदेशक ने पहले ही दे दिया था इस्तीफा

मुंबई, प्रेट्र : अस्थायी तौर पर बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने शुक्रवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल में एतिहाद एयरवेज के नामित सदस्य रॉबिन कमार्क ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 16 मई से प्रभावी है। कमार्क के इस्तीफे के बाद जेट एयरवेज के निदेशक मंडल में केवल अशोक चावला और शरद शर्मा बचे रह गए हैं। एतिहाद ने 2013 में जेट एयरवेज में 24 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी और कंपनी के बोर्ड में दो नामित निदेशकों रॉबिन कमार्क और केविन नाइट को नियुक्त किया था।

नाइट ने मार्च में ही इस्तीफा दे दिया था, जब कंपनी के संस्थापक-चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने कर्ज पुनर्गठन योजना के तहत 25 मार्च को इस्तीफा दिया था।

जेट एयरवेज एक माह में 24 फीसद से अधिक टूटा

नई दिल्ली : जेट एयरवेज के विमानों का परिचालन बंद होने के बाद गत एक महीने में कंपनी के शेयरों में 24.28 फीसद गिरावट आई है। कंपनी ने नकदी के अभाव में 18 अप्रैल से विमानों का परिचालन बंद कर दिया है। शुक्रवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर 2.32 फीसद गिरकर 124.10 रुपये पर बंद हुए। गत बुधवार को कंपनी के शेयरों ने 120.25 रुपये का सालभर का निचला स्तर छू लिया था। पिछले एक महीने में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 451.26 करोड़ रुपये घटकर 1,409.74 करोड़ रुपये पर आ गया है।

जेट के विदेशी रूट का होगा पारदर्शी आवंटन

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन सचिव पीएस खरोला ने कहा कि जेट एयरवेज के फॉरेन फ्लाइंग राइट्स (विदेशी रूट) अस्थायी तौर पर दूसरी कंपनियों को देने के लिए मंत्रालय पारदर्शी मानक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा। वह जेट के विदेशी रूट के अस्थायी आवंटन पर केंद्रित एक बैठक के बाद बोल रहे थे। बैठक में विमानन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आम तौर पर दो देश समझौता के जरिये तय करते हैं कि हर सप्ताह कितने यात्री एक दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। इस साप्ताहिक सीट आवंटन को फॉरेन फ्लाइंग राइट्स कहा जाता है। इन सीटों को संबंधित देश की सरकार अपनी विमानन कंपनियों को आवंटित करती है।

श्रम, भूमि सुधार ही देंगे आर्थिक विकास को गति : एनके सिंह

- वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा – यह किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी निवेश की सुस्ती पर चिंता जताते हुए 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा है कि आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार को भूमि और श्रम समेत अन्य क्षेत्रों की चुनौतियों में सुधार की शुरुआत करनी चाहिए।

सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राजकोषीय सूझबूझ सतत दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लंबी अवधि की वृहत आर्थिक स्थिरता का मुख्य घटक है। एसोचैम के एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता उन चीजों में से एक है, जो कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। आर्थिक सुधार के मोर्चे पर सिंह ने कहा, 'उत्पादन के कारकों यानी श्रम, भूमि और पूंजी में सुधार की बेहद जरूरत है। इन तीनों क्षेत्रों में सुधार नहीं हुआ है। हम उत्पादन के कारकों में सुधार करने में अब तक विफल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि श्रम कानून अब भी जटिल है और दीर्घकालिक अनुबंध और विवाद समाधान जैसे कुछ मसलों पर फिर विचार करके सुधार लाने की जरूरत है।

भूमि अधिग्रहण बड़ा मसला : सिंह ने कहा कि इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और लागत के अलावा पूंजी लागत को निचले स्तर पर लाने की जरूरत है। सिंह ने कहा, 'वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी नहीं है। यह लगातार आई सरकारों के इन कठिन चुनौतियों को हल करने की अक्षमता से जुड़ी रही है। किसी भी नई सरकार की बात की जाए तो उसे सत्ता संभालने के पहले साल इन्हीं चुनौतियों से निपटना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा-शक्ति होनी चाहिए।'

मजबूत और स्थिर सरकार जरूरी

सिंह ने कहा, 'मुझे लगता है कि मजबूत और स्थिर सरकार चुनने के लिए जनता की बुद्धिमानी उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगी, जो उत्पादन के कारकों में कुछ सुधार लाएगी।' सिंह ने कर्ज और जीडीपी के बीच का अनुपात अधिक होने को लेकर कहा कि समूह के अन्य देशों की तुलना में यह अनुपात सही स्थान पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास इसे नीचे लाने पर है और केंद्र व राज्य सरकारें कर्ज जीडीपी अनुपात को निर्धारित स्तर पर लाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

कमजोर विदेशी रुझान व स्थानीय सुस्ती से सोना, चांदी फिसले

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजार के कमजोर रुझानों और घरेलू ज्वेलर्स के बीच खरीदारी घटने से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 160 रुपये फिसलकर 33,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटने के कारण चांदी भी 625 रुपये कमजोर होकर 37,625 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई। विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी बाजार के नकारात्मक रुझानों के कारण बहुमूल्य धातुओं की कीमत गिरी। स्थानीय मांग घटने का भी कीमत पर दबाव रहा। न्यूयॉर्क में सोने में 1,286.50 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 14.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 160 रुपये फिसलकर 33,170 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया।

सरकारी कंपनियों की निवेश नीति में बदलाव की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यों के उपक्रमों से निवेश निकालने की तैयारी
- घाटे वाले उपक्रमों में भी केंद्रीय कंपनियों का निवेश रुकेगा

सरकारी कंपनियां अब अपने निवेश को लेकर मनचाहे फैसले नहीं ले पाएंगी। खासतौर पर राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों और अपने कार्यक्षेत्र से बाहर की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने को लेकर सरकारी कंपनियों की निवेश नीति में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद सरकारी कंपनियों की निवेश नीति में बदलाव से संबंधित नए दिशानिर्देशों का एलान हो सकता है।

सरकारी कंपनियों के निवेश की पुनर्संरचना को लेकर काफी समय से विचार चल रहा है। खासतौर पर राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों में केंद्रीय पीएसयू के निवेश को लेकर केंद्रीय मंत्रालयों में सवाल उठ रहे थे। कई कंपनियों के निवेश अब घाटे का सौदा हो गए हैं। इसे देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे निवेश पर सवाल भी उठाए। इसलिए सरकार ने इन उपक्रमों को ऐसे उद्यमों से निकलने का मौका देने का फैसला किया है।

राज्यों के उपक्रमों के अलावा केंद्रीय सरकारी कंपनियां अन्य केंद्रीय उपक्रमों में भी निवेश करती रही हैं। कई बार मुनाफे वाले उपक्रमों को घाटे में चल रहे उपक्रमों में न केवल निवेश करना पड़ता है, बल्कि उनके साथ संयुक्त उद्यम भी लगाने पड़ते हैं। सरकार इस तरह के निवेश से भी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बाहर लाना चाहती है। यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय पीएसयू की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश के तहत की जा रही है। इसका लाभ इन उपक्रमों में विनिवेश के वक्त मिल सकता है।

ट्रेड वार से चीन के विकास दर को एक फीसद की चोट

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलितब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने किया स्वीकार
- चीन की सरकार का आकलन, आर्थिक विकास सरकारी अनुमान से एक फीसद रह सकता है कम

बीजिंग, प्रेट्र : अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को एक फीसद का नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान को चीन की पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ जारी तकरार से उसे नुकसान हो रहा है। चीन की आर्थिक विकास दर पिछले साल 6.8 फीसद रही थी। इस साल के लिए सरकार ने विकास अनुमान को घटाकर 6-6.5 फीसद के दायरे में रखा है।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलितब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सात सदस्यों में से एक वांग यांग ने कहा कि अमेरिका-चीन ट्रेड वार इस साल चीन के अनुमानित आर्थिक विकास को पूरे एक फीसद का नुकसान पहुंचाएगा। वांग यांग का बयान हांगकांग के समाचार पत्र साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट में प्रकाशित हुआ है।

ताईवान के कुछ कारोबारियों से बातचीत में वांग ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने एक साल के व्यापार युद्ध के प्रभाव का आकलन किया है। इसके मुताबिक सबसे अधिक बुरा असर यह हो सकता है कि देश की विकास दर सरकार के अनुमान से एक फीसद कम रह सकती है। चीन की शीर्ष नीति निर्मात्री समिति में वह पहले अधिकारी हैं, जिन्होंने व्यापार युद्ध के नकारात्मक असर को खुलकर स्वीकार किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल से चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ रखा है। ट्रंप की चीन से मांग है कि वह द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी व्यापार घाटे में कमी लाए। वह चीन की सरकार से बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) की सुरक्षा और चीन के बाजार में अमेरिकी वस्तुओं को और अधिक प्रवेश देने के लिए भी कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं।

हुआवे अमेरिका की शिकायत दूर करने के लिए तैयार

सैन फ्रांसिस्को : अमेरिका में प्रतिबंध का सामना कर रही चीन की कंपनी हुआवे ने कहा कि उसने अमेरिका की सुरक्षा चिंता को दूर करने के लिए अपने विकल्प खुले रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों पर ऐसे विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने हुआवे और उसकी दर्जनों सहायक इकाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम मानी जाने वाली कंपनियों की सूची में डाल दिया है।

बाधा

ईपीएस पेंशन पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा ईपीएफओ, पूरे वेतन से ईपीएस योगदान के हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट सही बता चुका है

निजी क्षेत्र में बेहतर पेंशन की राह आसान नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ईपीएस पेंशन योजना के तहत सम्मानजनक पेंशन पाने की उम्मीद कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को झटका लग सकता है। ईपीएस पर केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने वाले वाले फैसले के खिलाफ ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहा है। यह याचिका लोकसभा चुनावों के बाद कभी भी दाखिल हो सकती है।

केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ईपीएस स्कीम के तहत नियोक्ता का योगदान पूरे वेतन से किए जाने का आदेश दिया था और इस पर लागू 15,000 रुपये की सीमा को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ईपीएस स्कीम में बेहद मामूली पेंशन से निराश निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई थी, क्योंकि इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था। अभी 15,000 रुपये की सीमा के कारण निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद ईपीएस पेंशन के रूप में एक हजार रुपये से लेकर अधिकतम तीन हजार रुपये तक की पेंशन मिलती है, क्योंकि उक्त सीमा के कारण पेंशन कोष में नियोक्ता की ओर से अधिकतम 1,250 रुपये का योगदान किया जाता है। हाईकोर्ट ने 1995 के ईपीएस एक्ट के मूल प्रावधान का हवाला देते हुए इसे गलत माना और 2014 में किए गए उस संशोधन को खारिज कर दिया जिसके तहत योगदान के लिए वेतन पर 15,000 रुपये की सीमाबंदी लागू कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईपीएस के तहत नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के पूरे वेतन से लिया जाएगा और इसके लिए अंतिम वर्ष के औसत मासिक वेतन को आधार बनाया जाएगा।

कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए अभी हर महीने कर्मचारी के वेतन का 12 फीसद हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि इतनी ही रकम नियोक्ता द्वारा जमा कराई जाती है।

यही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन देने के इरादे से ईपीएफओ नियोक्ता के योगदान में से 8.33 प्रतिशत रकम कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के खाते में हस्तांतरित करता है। अभी 15,000 रुपये की सीमाबंदी के कारण ये रकम अधिकतम 1,250 रुपये बैठती है। इस रकम से ईपीएस का जो कोष बनता है उससे 1,000-3,000 रुपये से ज्यादा पेंशन देना संभव नहीं है। परंतु हाई कोर्ट के फैसले से स्थिति बदल गई है हालांकि इससे ईपीएस कोष तो बढ़ जाएगा, किंतु ईपीएफ कोष घट जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ईपीएस योगदान की गणना कर्मचारी के सेवा में आने वाले महीने के वेतन से शुरू कर सेवा के आखिरी महीने के वेतन के अनुसार की जाएगी।

संगठन को डर भी : ईपीएफओ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी अवश्य कर रहा है। लेकिन उसे इसके भी खारिज होने का डर भी बराबर सता रहा है। इस बीच ईपीएस पेंशन पर कोर्ट के फैसलों के बाद देश भर में निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारी और हजारों नियोक्ता पेंशन बढ़ने की उम्मीद में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

ईपीएफओ का तर्क

ईपीएफओ का कहना है कि पूरे वेतन से ईपीएस योगदान से कर्मचारी की पेंशन अवश्य कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसे लागू करने से ईपीएस कोष पर दबाव बढ़ जाएगा। संगठन के मुताबिक पेंशन गणना का फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। ईपीएस पेंशन की गणना एक फार्मूले के अनुसार की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस कोष की स्थिति को समझे बगैर फैसले दिए हैं।

जेपी इन्फ्रा के लिए हुई वोटिंग रद

नई दिल्ली, प्रेट्र : जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए जमा की गई एनबीसीसी की संशोधित बोली पर घर खरीदारों और कर्जदाताओं की वोटिंग को नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने शुक्रवार को रद कर दिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोली पर 30 मई तक फिर से सौदेबाजी की अनुमति दे दी। एनबीसीसी की बोली पर वोटिंग गुरुवार को शुरू हुई थी, जो रविवार को खत्म होनी थी और इसके परिणाम की घोषणा 20 मई को होनी थी। आइडीबीआइ बैंक ने इस वोटिंग पर रोक लगाने या इसे रद किए जाने के लिए आवेदन किया था।

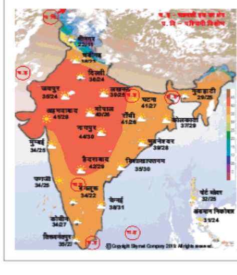

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी तथा एक-दो स्थानों पर ओला वृष्टि होने की संभावना है। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गरज और तेज हवाओं के साथ आंधी तथा हल्की वर्षा होने के आसार है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/25/धू	अहमदाबाद	43/24/आंधी
कोलकाता	37/29/आंधी	बड़ौदा	43/25/आंधी
चेन्नई	37/29/आंधी	नागपुर	45/30/धू
हैदराबाद	43/30/धू	इन्दौर	43/28/धू
बेंगलूरु	34/23/धू	रांची	43/27/धू
तिरुवनंतपुरम	35/26/आंधी	पटना	40/27/आंधी
गुवाहाटी	30/24/आंधी	जमशेदपुर	38/29/धू
गंगटोक	15/06/धू	पुणे	26/21/धू